भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1570

उत्तर देने की तारीख 09 फरवरी, 2026

सोमवार, 20 माघ, 1947 (शक)

क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स में भारत की स्थिति

1570. श्री कल्याण बनर्जी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत 25वें स्थान पर है और "फ्यूचर ऑफ वर्क" श्रेणी में दूसरे स्थान पर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल रोजगार क्षमता में उच्च स्थान (2022 में चौथे) और एसडीजी सूचकांक 2023-24 में 91.38 प्रतिशत संख्यात्मक कौशल के साथ "फ्रन्ट रनर" के रूप में मान्यता प्राप्त होने और देश में प्रशिक्षुता चाहने वालों की सबसे अधिक संख्या के कारण मजबूत वृद्धि दर्शाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्यों को उनकी रैंकिंग के अनुसार सुदृढ़ करने और उनमें महिला कार्यबल में वृद्धि करने के लिए क्या रणनीतिक पहल की गई है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 का उद्देश्य वैश्विक कार्यबल की बदलती मांगों को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से डिजिटल परिवर्तन, एआई, स्थिरता और नौकरियों को प्रभावित करने वाले व्यापक आर्थिक परिवर्तनों के संदर्भ में देशों के तैयारी का आकलन करना है । यह सूचकांक एक तेजी से बढ़ रही कौशल-आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश की तैयारी को मापने के लिए चार संकेतकों का उपयोग करता है: -

कार्य का भविष्य: कार्य का भविष्य सूचक किसी देश के रोजगार बाजार की भविष्य में सबसे अधिक मांग वाले कौशलों के लिए भर्ती करने की तत्परता को मापता है। भारत ने 99.1 अंक प्राप्त किए, जो अमेरिका से ठीक पीछे दूसरे स्थान पर है। भारत कार्य के भविष्य में योगदान देने वाले अग्रणी देशों में से एक है।

कौशल अनुकूलता: कौशल अनुकूलता इस बात का मापन करती है कि किसी देश की शिक्षा प्रणाली नियोक्ताओं की मांगों के साथ कितनी अच्छी तरह मेल खाती है। भारत ने 59.1 अंक प्राप्त किए।

शैक्षणिक तत्परता: शैक्षणिक तत्परता इस बात का मापन करती है कि कोई देश भविष्य के उद्योगों के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने में कितना सक्षम है। भारत ने 89.9 अंक प्राप्त किए।

आर्थिक परिवर्तन: आर्थिक परिवर्तन सूचक यह मापता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कौशल-आधारित औद्योगिक विकास की अगली लहर का लाभ उठाने के लिए कितनी तैयार है। भारत ने 58.3 अंक प्राप्त किए।

(ख): सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के समग्र सूचकांक, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में पश्चिम बंगाल ने 100 में से 70 अंक प्राप्त किए, जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 के 62 अंकों से 8 अंक अधिक है। इसके साथ ही यह 'परफॉर्मर' श्रेणी से 'फ्रंट रनर' श्रेणी में आ गया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में राज्य ने 28 राज्यों में से 17वां स्थान प्राप्त किया, जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 के अपने स्थान को बरकरार रखे हुए है। वर्तमान में, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में ऐसे कोई सूचक नहीं हैं जो संख्यात्मक कौशल या इंटर्नशिप चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाते हों। एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अब तक चार संस्करण जारी किए जा चुके हैं। नवीनतम संस्करण https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2024-07/SDG India Index_2023-24.pdf पर उपलब्ध है।

(ग): भारत सरकार ने कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं सहित देश के युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार लाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा देश भर में समाज के सभी वर्गों, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, को कौशल, पुनर्कौशलीकरण और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल भारत मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उन्हें उद्योग-प्रासंगिक कौशल से सुसज्जित करना है।

इसके अलावा, कौशल विकास कार्यक्रमों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, परिवहन और आवास एवं भोजन पर होने वाले खर्च को पूरा करने के साथ-साथ नियुक्ति के बाद बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। पीएमकेवीवाई 4.0 उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है और उन पर विशेष ध्यान देता है जिनमें महिलाओं को प्राथमिक लाभार्थी माना जाता है। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत विशेष

परियोजनाएं स्थानीय कौशल मांगों के अनुरूप बनाई गई हैं, जिससे ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास योजनाओं में भाग लेने और उनसे लाभ उठाने के अवसर मिलते हैं। यह समावेशी दृष्टिकोण देश भर में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व और लाभ सुनिश्चित करता है। एनएपीएस के तहत, सेवा क्षेत्र में ट्रेडों (वैकल्पिक ट्रेड) की शुरुआत से शिक्षुता में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जेएसएस योजना के तहत, महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसएस के तहत लाभार्थियों में 80% से अधिक महिलाएं हैं। साथ ही, 19 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) और 300 से अधिक आईटीआई विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं।

एमएसडीई ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से 'नव्या' नामक एक संयुक्त पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण करना है। नव्या एक प्रायोगिक पहल है जिसका लक्ष्य 16-18 वर्ष की किशोरियों को, जिन्होंने कम से कम कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की हो, मुख्य रूप से गैर-पारंपरिक रोजगार भूमिकाओं (जॉब रोल्स) में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।

*****